



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2016/ श्रावण 3, 1938

No. 246]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2016/ SRAVANA 3, 1938

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016

सं.1-2/2016-आईसी.— भारत सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (आयोग) का गठन 28 फरवरी, 2014 के संकल्प सं.1/1/2013-ई.III (ए) के तहत किया था। आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि 8 सितंबर, 2015 के संकल्प सं.1/1/2013-ई.III (ए) के तहत 31 दिसंबर, 2015 तक बढ़ा दी गई थी। आयोग ने 28 फरवरी, 2014 के उपर्युक्त संकल्प में यथा-विनिर्दिष्ट अपने विचारार्थ-विषयों में शामिल मामलों पर अपनी रिपोर्ट 19 नवम्बर, 2015 को प्रस्तुत की।

2. सरकार ने, विचार-विमर्श के पश्चात्, 28 फरवरी, 2014 के उपर्युक्त संकल्प में निहित विचारार्थ-विषयों में शामिल वर्गों के कर्मचारियों के संबंध में आयोग की सिफारिशें, इसमें आगे विनिर्दिष्ट रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

3. सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वेतन के साथ समानता बनाए रखने की दृष्टि से रक्षा वेतन मैट्रिक्स में निम्नलिखित अपवादों के साथ न्यूनतम वेतन, फिटमेंट गुणांक, पुनर्गठन सूचकांक, वेतन मैट्रिक्स के संबंध में और वेतन के संबंध में आयोग की आम सिफारिशें किसी बड़े परिवर्तन के बगैर स्वीकार कर ली हैं:-

- (i) रक्षा वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13ए (ब्रिगेडियर) का पुनर्गठन सूचकांक 2.57 से बढ़ाकर 2.67 कर दिया जाए।
- (ii) रक्षा वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12ए (लेफ्टिनेंट कर्नल) में 3 अतिरिक्त प्रक्रम, लेवल 13 (कर्नल) में 3 प्रक्रम और लेवल 13ए (ब्रिगेडियर) में 2 प्रक्रम उपयुक्त रूप से जोड़े जाएं।

4. (1) इस संकल्प के अधिसूचित किए जाने से ठीक पहले, सिविल कर्मचारियों के संबंध में लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स **उपाबंध-I** में यथा-विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स होगा।

(2) जहां तक 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार नए वेतन मैट्रिक्स में किसी कर्मचारी के वेतन निर्धारण का संबंध है, तो 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार संशोधन-पूर्व संरचना में विद्यमान वेतन (वेतन बैंड में वेतन जमा ग्रेड वेतन) को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त राशि, नए वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इस प्रकार प्राप्त राशि के समरूप कोई कोष्ठिका समुचित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा; अन्यथा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा।

(3) उक्त उप-पैरा (2) में यथा-विनिर्दिष्ट उपयुक्त लेवल में वेतन के निर्धारण के पश्चात् उसी लेवल में अगली वेतन वृद्धि, उस लेवल में दी गई उससे ठीक अगली कोष्ठिका में दी जाएगी।

5. विद्यमान 01 जुलाई की तारीख के बजाए वेतन वृद्धि दिए जाने की दो तारीखें होंगी नामतः प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई; शर्त यह है कि नियुक्ति, पदोन्नति अथवा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने की तारीख पर निर्भर करते हुए कोई कर्मचारी इन दो तारीखों में से केवल किसी एक तारीख पर वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

6. केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों के लिए संशोधित वेतन संरचना के संबंध में आयोग की सिफारिशों और उन पर सरकार का **उपाबंध-I** में यथा-उल्लिखित निर्णय तथा **उपाबंध-II** में यथा-उल्लिखित परिणामी वेतन निर्धारण, 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा। इस मद में बकाया राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2016-17 में किया जाएगा।

7. भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) से संबंधित सिफारिशों वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित एक समिति को भेजी जाएंगी जिसमें गृह, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डाक विभाग के सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति चार माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक, सभी भत्तों का भुगतान वर्तमान वेतन संरचना में विद्यमान दरों पर किया जाता रहेगा मानो कि वेतन 01 जनवरी, 2016 से संशोधित ही न किया गया हो।

8. ब्याज-युक्त अग्रिमों और ब्याज-मुक्त अग्रिमों के संबंध में आयोग की सिफारिशों इस अपवाद के साथ स्वीकार कर ली गई हैं कि चिकित्सा उपचार, मृतक के परिवार के लिए यात्रा भत्ते, दौरे अथवा स्थानांतरण पर यात्रा भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम जारी रखे जाएंगे।

9. विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में मासिक अंशदान की दरों में वृद्धि की आयोग की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। मासिक अंशदान की विद्यमान दरें जारी रहेंगी। व्यय विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक उपयुक्त सामूहिक बीमा योजना तैयार करेंगे।

10. सरकार ने उन पदों जिनका उल्लेख **उपाबंध-III** में किया गया है, को छोड़कर, पदों के उन्नयन के संबंध में आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। उन्नयन के संबंध में **उपाबंध-III** में वर्णित सिफारिशों की जांच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अलग से की जाएगी ताकि इस मामले पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

11. सरकार ने पदावनति संबंधी आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं और ऐसे मामलों में सामान्य प्रतिस्थापन दिया जाएगा।
12. चिकित्सकों जिनके लिए प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है और रेलवे कर्मचारियों जिनके लिए चलन भत्ता स्वीकार्य है, के वेतन संशोधित करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रारंभिक निर्धारण के समय वेतन में वास्तविक वृद्धि आयोग द्वारा यथा-संस्तुत लगभग 14.29% हो।
13. केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की वेतन-रक्षा की जाएगी और उन्हें वेतन में अंतर का भुगतान अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा।
14. ऐसी सिफारिशों जो वेतन, पेंशन एवं भत्तों से संबंधित नहीं हैं, की जांच तथा विभागों/संवर्गों/पदों से विशिष्ट तौर पर जुड़े अन्य प्रशासनिक मुद्दों संबंधी सिफारिशों की जांच संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्य आबंटन नियमों/कारबार संव्यवहार नियमों के अनुसार की जाएगी। जब तक (i) भारतीय पुलिस सेवा/ भारतीय वन सेवा और संगठित समूह "क" सेवाओं में वर्तमान में स्वीकार्य गैर-कार्यात्मक उन्नयन, (ii) केन्द्रीय स्टॉफिंग स्कीम के तहत पैनल में शामिल किए जाने के संदर्भ में अन्य अखिल भारतीय सेवाओं/संगठित समूह "क" सेवाओं की तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दो वर्ष की अग्रता, (iii) भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के बराबर सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और सेलेक्शन ग्रेड में दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने, (iv) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सभी रैंक के लिए एक समान सेवानिवृत्ति आयु से संबंधित प्रशासनिक मुद्दों जिन पर आयोग सर्वसम्मति नहीं बना सका है, के बारे में सरकार द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक यथा स्थिति बनी रहेगी।
15. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के उपाय सुझाने के लिए सचिवों की एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कार्मिक और प्रशिक्षण, वित्तीय सेवाएं तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव शामिल होंगे।
16. आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद-विशिष्ट और संवर्ग-विशिष्ट विसंगतियों की जांच के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विसंगति समितियों का गठन किया जाएगा।
17. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित वेतन और उससे जुड़े मामलों के बारे में उचित कार्रवाई कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जाएगी जिससे कि इन मामलों में लिये गए तथा उन सेवाओं पर प्रयोज्य निर्णयों को लागू किया जा सके।
18. भारत सरकार, आयोग द्वारा किए गए कार्य के लिए आयोग की सराहना करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेजी जाए।

आर.के. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

उपाबंध- I

वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैंड	5200-20200					9300-34800				15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000	90000
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13क	14	15	16	17	18
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000	250000
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600		
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900		
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400		
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100			
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300			
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600			
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100			
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	150200	166100	182700				
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	154700	171100	188200				
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	159300	176200	193800				
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	164100	181500	199600				
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	169000	186900	205600				
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	174100	192500	211800				
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	179300	198300	218200				
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	184700	204200					
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	190200	210300					
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	195900	216600					
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	201800						
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	207900						
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400	214100						
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700							
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100							
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600							
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300							
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100							
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100							
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200							
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500							

वेतन बैंड	5200-20200					9300-34800				15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000	90000
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13क	14	15	16	17	18
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900	132000	160000	185900							
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600	136000	164800	191500							
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500	140100	169700	197200							
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500	144300	174800	203100							
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600	148600	180000	209200							
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800	153100	185400								
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100	157700	191000								
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600	162400	196700								
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200	167300	202600								
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900	172300	208700								
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800	177500									

उपाबंध-II

समूह 'क', 'ख' और 'ग' के सिविल कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों से संबंधित वेतन के बारे में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णयों को दर्शाने वाला विवरण।

I. संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण:

क्र. सं.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1.	01.01.2016 से सरकार में न्यूनतम वेतन 18000 रुपए प्रति माह (रिपोर्ट का पैरा 4.2.13)	स्वीकृत
2.	वेतन मैट्रिक्स के दो आयाम हैं - इसकी क्षैतिज परास जिसमें 1, 2, 3 से लेकर 18 तक संख्या दी गई है और जिसका प्रत्येक लेवल 'पद क्रम में कार्यात्मक भूमिका' के अनुरूप तय है तथा 'लम्बवत् परास' जिसमें 'वेतन अनुक्रम' दर्शाया गया है। इनसे वार्षिक वित्तीय अनुक्रम के सोपानों का पता चलता है (रिपोर्ट का पैरा सं. 5.1.21)	स्वीकृत
3.	भर्ती होने पर, कर्मचारी किसी लेवल विशेष पर कार्यभार ग्रहण करता है और लम्बवत् परास के अनुसार उसी लेवल में आगे बढ़ता है। सामान्यतः यह संचलन, उसकी अगली पदोन्नति के समय तक वार्षिक वेतन वृद्धियों के आधार पर वार्षिक आधार पर होता रहता है (रिपोर्ट का पैरा 5.1.22)	स्वीकृत
4.	2.57 का फिटमेंट गुणांक सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाए (रिपोर्ट का पैरा 5.1.27)	स्वीकृत
5.	कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.28 और 5.1.29 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए।	स्वीकृत
6.	आयोग द्वारा संस्तुत पदों के उन्नयन के मामले में वेतन, रिपोर्ट के पैरा 5.1.30 में निर्धारित विधि से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाए।	स्वीकृत। पदावनति संबंधी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई और इसीलिए, पदावनति पर वेतन निर्धारण का कोई अवसर मौजूद नहीं है।
7.	सीधी भर्ती से आए कार्मिकों का वेतन उस लेवल जिस पर	स्वीकृत

	उनकी भर्ती की गई है, में दिए गए अनुरूपी न्यूनतम वेतन से शुरू होगा; यह न्यूनतम वेतन, मैट्रिक्स में प्रत्येक लेवल की प्रथम कोष्ठिका में उल्लिखित वेतन होगा। (रिपोर्ट का पैरा 5.1.32)	
8.	पदोन्नति पर कर्मचारियों का वेतन रिपोर्ट के पैरा 5.1.33 में वर्णित विधि से निर्धारित किया जाए।	स्वीकृत

II. वार्षिक वेतन वृद्धि:

क्र. सं.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1.	वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने की विधि, रिपोर्ट के पैरा 5.1.53 में यथानिर्धारित विधि होगी।	स्वीकृत

III. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम:

क्र. सं.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1.	एमएसीपी पहले की तरह 10, 20 और 30 वर्ष पर दी जाती रहेगी। नए वेतन मैट्रिक्स में, कर्मचारी पदक्रम में ठीक अगले लेवल में चला जाएगा। वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के लिए वही सिद्धांत अपनाया जाएगा जो नियमित पदोन्नति के लिए अपनाया जाता है। एमएसीपी स्कीम संगठित समूह 'क' सेवाओं के सदस्यों को छोड़कर उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) स्तर तक सभी कर्मचारियों के लिए लागू बनी रहेगी। (रिपोर्ट का पैरा 5.1.44)	स्वीकृत
2.	एमएसीपी स्कीम के तहत प्रोन्नति और वित्तीय उन्नयन के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का मानदंड 'अच्छा' से बढ़ाकर 'बहुत अच्छा' किया जाए। (रिपोर्ट का पैरा 5.1.45)	स्वीकृत
3.	ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो अपनी सेवा के प्रथम 20 वर्षों में एमएसीपी अथवा नियमित पदोन्नति के मानदंड को पूरा नहीं कर पाते, वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाए। (रिपोर्ट का पैरा 5.1.46)	स्वीकृत

IV. विनियामक निकायों में समेकित वेतन पैकेज:

क्र. सं.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1.	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियमन प्राधिकरण के अध्यक्षों के लिए 4,50,000 रुपए (चार लाख पचास हजार रुपए मात्र) का समेकित वेतन पैकेज (रिपोर्ट का पैरा 13.15.(i))	स्वीकृत
2.	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियमन प्राधिकरण के सदस्यों के लिए 4,00,000 रुपए (चार लाख रुपए मात्र) का समेकित वेतन पैकेज (रिपोर्ट का पैरा 13.15.(i))	स्वीकृत
3.	महंगाई भत्ता जब भी 50% बढ़ जाए तो उपर्युक्त मामलों में समेकित वेतन पैकेज में 25% की वृद्धि कर दी जाए। दौरे पर यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता सहित अन्य सभी लाभ विनियामक निकायों द्वारा अपने नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए जाएं। (रिपोर्ट का पैरा 13.15.(ii))	स्वीकृत
4.	संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित शेष विनियामक निकायों के विद्यमान सदस्यों के लिए सामान्य प्रतिस्थापन वेतन (रिपोर्ट का पैरा 13.15.(iii))	स्वीकृत

V. महंगाई भत्ता:

क्र. सं.	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1.	महंगाई भत्ते की गणना के लिए मौजूदा फार्मूला और	स्वीकृत। संशोधित वेतन संरचना

	कार्यप्रणाली जारी रखी जाए (रिपोर्ट का पैरा 8.17.37)	लागू होने के बाद महंगाई भत्ते की गणना के लिए संदर्भ आधार में तदनुसार परिवर्तन किया जाएगा और उसे 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार औसत सूचकांक से जोड़ा जाएगा।
--	---	--

उपाबंध- III

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत पदोन्नयन के मामलों की सूची, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी जानी है

क (I) शीर्ष लेवल से भिन्न उन्नयन:

क्र. सं.	पद का नाम (सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट का पैरा सं.)	वर्तमान ग्रेड वेतन	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत ग्रेड वेतन
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन का कनिष्ठ रेडियोग्राफर (7.7.50)	2000	2800
2.	परिरक्षण सहायक, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (11.16.19)	2000	2400
3.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण), खान मंत्रालय (11.29.15)	4200	4600
4.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्राईंग), खान मंत्रालय (11.29.15)	4200	4600
5.	तकनीकी अधिकारी, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय (11.49.9)	4200	4600
6.	सहायक निदेशक ग्रेड-II (तकनीकी), वस्त्र मंत्रालय (11.49.9)	4600	4800
7.	सहायक लेखा अधिकारी, रक्षा वित्त प्रभाग, रक्षा मंत्रालय (11.12.140)	4800	सेवा के चार वर्ष पूरे होने के पश्चात् 5400

8.	वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), रेल मंत्रालय (11.40.83)	4800	(पीबी-2)
9.	वरिष्ठ सचल निरीक्षक (लेखा), रेल मंत्रालय (11.40.83)	4800	
10.	वरिष्ठ निरीक्षक (भंडार लेखा), रेल मंत्रालय (11.40.83)	4800	
11.	रसायन और धातुविज्ञान सहायक (सीएमए) रेल मंत्रालय (11.40.124)	4200	4600
12.	रसायन और धातुविज्ञान अधीक्षक (सीएमएस), रेल मंत्रालय (11.40.124)	4600	4800
13.	सहायक रसायनज्ञ और धातु विज्ञानी, रेल मंत्रालय (11.40.124)	4800	5400 (पीबी-2)

क (II) शीर्ष वेतनमान में उन्नयन:

क्र.सं.	पद का नाम (सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट का पैरा सं.)
1.	महानिदेशक (भारतीय तट रक्षक) (11.12.27)
2.	महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (11.47.9)
3.	आयकर न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष, विधि कार्य विभाग (11.27.27)
4.	प्रमुख, राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (एनडीसी), नई दिल्ली (14.21)
5.	प्रमुख, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खडकवासला, पुणे (14.21)
6.	प्रमुख, रक्षा सेवा स्टाफ कालेज (डीएसएससी), वैलिंग्टन (14.21)

ख. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत मामले जिनमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है:

क्र. सं.	पद का नाम (सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट का पैरा सं.)	वर्तमान ग्रेड वेतन	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत ग्रेड वेतन	टिप्पणी
----------	--	--------------------	--	---------

1.	कृषि सहायक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (11.23.170)	2400	2800	पद मौजूद नहीं हैं।
2.	माली ओवरसीयर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (11.23.170)	2400	2800	
3.	ग्रुप लेवल वर्कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (11.23.170)	2400	2800	
4.	विस्तार अधिकारी (कृषि) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (11.23.170)	2400	2800	
5.	कनिष्ठ फार्म प्रबंधक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (11.23.170)	2400	2800	
6.	सहायक भंडारपाल, भारतीय खान ब्यूरो (11.29.24)	1900	2400	यह पद पहले से ही 2400 रुपए के ग्रेड वेतन में है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th July, 2016

No. 1-2/2016-IC.— The Seventh Central Pay Commission (Commission) was set up by the Government of India vide Resolution No. 1/1/2013-E.III (A), dated the 28th February, 2014. The period for submission of report by the Commission was extended upto 31st December, 2015 vide Resolution No. 1/1/2013-E.III(A), dated the 8th September, 2015. The Commission, on 19th November, 2015, submitted its Report on the matters covered in its Terms of Reference as specified in the aforesaid Resolution dated the 28th February, 2014.

2. The Government, after consideration, has decided to accept the recommendations of the Commission in respect of the categories of employees covered in its Terms of Reference contained in the aforesaid Resolution dated the 28th February, 2014 in the manner as specified hereinafter.

3. The Government has accepted the Commission's recommendations on Minimum Pay, Fitment Factor, Index of Rationalisation, Pay Matrices and general recommendations on pay without any material alteration with the following exceptions in Defence Pay Matrix in order to maintain parity in pay with Central Armed Police Forces, namely :-

- (i) the Index of Rationalisation of Level 13A (Brigadier) in Defence Pay Matrix may be revised upward from 2.57 to 2.67;
- (ii) additional three stages in Levels 12A (Lieutenant Colonel), three stages in Level 13 (Colonel) and two stages in Level 13A (Brigadier) may be added appropriately in the Defence Pay Matrix.

4. (1) The Pay Matrix, in replacement of the Pay Bands and Grade Pays as in force immediately prior to the notification of this Resolution, shall be as specified in **Annexure I** in respect of civilian employees.

(2) With regard to fixation of pay of the employee in the new Pay Matrix as on 1st day of January, 2016, the existing pay (Pay in Pay Band plus Grade Pay) in the pre-revised structure as on 31st day of December, 2015 shall be multiplied by a factor of 2.57. The figure so arrived at is to be located in the Level corresponding to employee's Pay Band and Grade Pay or Pay Scale in the new Pay Matrix. If a Cell identical with the figure so arrived at is available in the appropriate Level, that Cell shall be the revised pay; otherwise the next higher cell in that Level shall be the revised pay of the employee.

(3) After fixation of pay in the appropriate Level as specified in sub-paragraph (2) above, the subsequent increments in the Level shall be at the immediate next Cell in the Level.

5. There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July; provided that an employee shall be entitled to only one annual increment on either one of these two dates depending on the date of appointment, promotion or grant of financial up-gradation.

6. The Commission's recommendations and Government's decision thereon with regard to revised pay structure for civilian employees of the Central Government and personnel of All India Services as specified at **Annexure I** and the consequent pay fixation therein as specified at **Annexure II** shall be effective from the 1st day of January, 2016. The arrears on this account shall be paid during the financial year 2016-2017.

7. The recommendations on Allowances (except Dearness Allowance) will be referred to a Committee comprising Finance Secretary and Secretary (Expenditure) as Chairman and Secretaries of Home Affairs, Defence, Health and Family Welfare, Personnel and Training, Posts and Chairman, Railway Board as Members. The Committee will submit its report within a period of four months. Till a final decision on Allowances is taken based on the recommendations of this Committee, all Allowances will continue to be paid at existing rates in existing pay structure, as if the pay had not been revised with effect from 1st day of January, 2016.

8. The recommendations of the Commission relating to interest bearing Advances as well as interest free Advances have been accepted with the exception that interest free Advances for Medical Treatment, Travelling Allowance for family of deceased, Travelling Allowance on tour or transfer and Leave Travel Concession shall be retained.

9. The recommendations of the Commission for increase in rates of monthly contribution towards Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) for various categories of employees has not been accepted. The existing rates of monthly contribution shall continue. Department of Expenditure and Department of Financial Services will work out a customised group insurance scheme for Central Government employees.

10. The Government has accepted the recommendations of the Commission on upgrading of posts except for those specified at **Annexure III**. The recommendations on upgradation specified at **Annexure III** will be separately examined by Department of Personnel and Training for taking a comprehensive view in the matter.

11. The Government has not accepted the recommendations of the Commission on downgrading of posts and normal replacement will be provided in such cases.
12. While revising the pay of Doctors in respect of whom Non Practicing Allowance is admissible and Railway employees in respect of whom Running Allowance is admissible, it will be ensured that the actual raise in pay at the time of initial fixation is about 14.29 percent as recommended by the Commission.
13. The pay of officers posted on deputation under Central Staffing Scheme will be protected and the difference in the pay will be given to them in the form of Personal Pay to be made effective from the date of notification.
14. Recommendations not relating to pay, pension and allowances and other administrative issues specific to Departments/Cadres/Posts will be examined by the Ministries/Departments concerned as per the Allocation of Business Rules or Transaction of Business Rules. Until a decision is taken by the Government on administrative issues pertaining to (i) Non Functional Upgradation (NFU) presently admissible to the Indian Police Service/Indian Forest Service and Organised Group 'A' Services, (ii) two years' edge to Indian Administrative Service officers vis-a-vis other All India Services/Organised Group 'A' Services in empanelment under Central Staffing Scheme, (iii) grant of two additional increments at Senior Time Scale, Junior Administrative Grade and Selection Grade to Indian Police Service and Indian Forest Service at par with Indian Administrative Service and Indian Foreign Service (iv) a uniform retirement age for all ranks in Central Armed Police Forces, where the Commission could not arrive at a consensus, status quo shall be maintained.
15. A Committee of Secretaries comprising Secretaries of Departments of Personnel and Training, Financial Services and Pension and Pensioners' Welfare will be set up to suggest measures for streamlining the implementation of the National Pension System (NPS).
16. Anomalies Committees will be set up by Department of Personnel and Training to examine individual, post-specific and cadre-specific anomalies arising out of implementation of the recommendations of the Commission.
17. Regarding pay and related issues concerning All India Services, appropriate action will be taken by Department of Personnel and Training to give effect to the decisions on these matters as may be applicable to them.
18. The Government of India wishes to place on record their appreciation of the work done by the Commission.

ORDER

Ordered that this Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary.

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories and all other concerned.

R.K. CHATURVEDI, Jt. Secy.

Annexure I

PAY MATRIX

Pay Band	5200-20200					9300-34800				15600-39100			37400-67000			67000-79000	75500-80000	80000	90000
	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400	5400	6600	7600	8700	8900	10000				
Grade Pay																			
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13₹	14	15	16	17	18
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100	56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200	205400	225000	250000
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700	57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	211600		
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300	59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	217900		
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000	61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	224400		
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700	63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100			
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500	65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300			
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300	67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600			
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200	69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100			
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200	71100	85800	99800	150200	166100	182700				
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200	73200	88400	102800	154700	171100	188200				
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300	75400	91100	105900	159300	176200	193800				
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400	77700	93800	109100	164100	181500	199600				
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600	80000	96600	112400	169000	186900	205600				
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900	82400	99500	115800	174100	192500	211800				
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200	84900	102500	119300	179300	198300	218200				
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600	87400	105600	122900	184700	204200					
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100	90000	108800	126600	190200	210300					
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700	92700	112100	130400	195900	216600					
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300	95500	115500	134300	201800						
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000	98400	119000	138300	207900						
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800	101400	122600	142400	214100						
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700	104400	126300	146700							
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700	107500	130100	151100							
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800	110700	134000	155600							
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900	114000	138000	160300							
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100	117400	142100	165100							
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400	120900	146400	170100							
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800	124500	150800	175200							
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300	128200	155300	180500							

ANNEXURE II

Statement showing the recommendations of the Seventh Central Pay Commission on Pay relating to Civilian employees in Group 'A', 'B' and 'C' and personnel of All India Services and Government's decisions thereon.

I. Pay Fixation in revised Pay Structure:

Sl. No.	Recommendation of the Seventh Central Pay Commission	Decision of the Government
1.	Minimum pay in government with effect from 01.01.2016 at Rs. 18000 per month (Para 4.2.13 of the Report)	Accepted
2.	Pay Matrix comprising two dimensions having horizontal range in which each level corresponds to a "functional role in the hierarchy" with number assigned 1, 2, 3 and so on till 18 and "vertical range" denoting "pay progression". These indicate the steps of annual financial progression (Para 5.1.21 of the Report)	Accepted
3.	On recruitment, an employee joins at a particular level and progresses within the level as per the vertical range. The movement is usually on an annual basis, based on annual increments till the time of their next promotion. (Para 5.1.22 of the Report)	Accepted
4.	The fitment factor of 2.57 to be applied uniformly for all employees. (Para 5.1.27 of the Report)	Accepted
5.	Pay of employees to be fixed in the revised Pay Structure in the manner laid down in Paras 5.1.28 and 5.1.29 of the Report.	Accepted
6.	In case of upgrading of posts recommended by the Commission, the pay may be fixed in revised Pay Structure in manner laid down in Para 5.1.30 of the Report.	Accepted. The recommendation regarding downgrading not accepted and, therefore, no occasion for fixation on downgrading of posts.
7.	Pay of direct recruits will start at the minimum pay corresponding to the Level to which recruitment is made, which will be the first cell of each Level in the Matrix (Para 5.1.32 of the Report)	Accepted
8.	On promotion, pay of employees to be fixed in the manner laid down in Para 5.1.33 of the Report.	Accepted

II. Annual Increments:

Sl. No.	Recommendation of the Seventh Central Pay Commission	Decision of the Government
1.	The manner of drawal of annual increment to be as laid down in Para 5.1.53 of the Report.	Accepted

III. Modified Assured Career Progression Scheme:

Sl. No.	Recommendation of the Seventh Central Pay Commission	Decision of the Government
1.	MACP will continue to be administered at 10, 20 and 30 years as before. In the new Pay Matrix, the employee will move to immediate next Level in hierarchy. Fixation of pay will follow the same principle as that for a regular promotion in the Pay Matrix. MACPS will continue to be applicable to all employees up to Higher Administrative Grade (HAG) level except members of Organised Group 'A' Services. (Para 5.1.44 of the Report)	Accepted
2.	Benchmark for performance appraisal for promotion and financial ungrdation under MACPS to be enhanced from "Good" to "Very Good". (Para 5.1.45 of the Report)	Accepted
3.	Withholding of annual increments in the case of those employees who are not able to meet the benchmark either for MACP or a regular promotion within the first 20 years of their service. (Para 5.1.46 of the Report)	Accepted

IV. Consolidated Pay package in Regulatory Bodies:

Sl. No.	Recommendation of the Seventh Central Pay Commission	Decision of the Government
1.	Consolidated pay package of Rs. 4,50,000 (Rupees Four Lakh and Fifty Thousand only) for Chairpersons of Telecom Regulatory Authority of India, Central Electricity Regulatory Commission, Insurance Regulatory and Development Authority, Securities and Exchange Board of India, Competition Commission of India, Pension Fund Regulatory and Development Authority, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, Warehousing Development and Regulatory Authority, and Airports Economic Regulatory Authority of India (Para No. 13.15 (i) of the Report)	Accepted

2.	Consolidated pay package of Rs. 4,00,000 (Rupees Four Lakh only) for Members of Telecom Regulatory Authority of India, Central Electricity Regulatory Commission, Insurance Regulatory and Development Authority, Securities and Exchange Board of India, Competition Commission of India, Pension Fund Regulatory and Development Authority, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, Warehousing Development and Regulatory Authority, and Airports Economic Regulatory Authority of India (Para No. 13.15 (i) of the Report)	Accepted
3.	Consolidated pay package in above cases to be raised by 25 percent as and when Dearness Allowance goes up by 50 percent. All other benefits, including Travelling Allowance/Daily Allowance on tour etc., to be provided by the Regulatory Bodies as per their rules and regulations. (Para No. 13.15 (ii) of the Report)	Accepted
4.	Normal replacement pay for existing Members of the remaining regulatory bodies set up under Acts of Parliament. (Para No. 13.15 (iii) of the Report)	Accepted

V. Dearness Allowance:

Sl. No.	Recommendation of the Seventh Central Pay Commission	Decision of the Government
1.	Existing formula and methodology for calculating Dearness Allowance to continue (Para 8.17.37 of the Report)	Accepted. The reference base for calculation of Dearness Allowance after coming into force of the revised Pay structure shall undergo change accordingly and will be linked to the average index as on 01.01.2016.

Annexure III

List of cases of upgradation of posts recommended by Seventh Central Pay Commission to be referred to Department of Personnel and Training

A (I). Upgradation other than Apex Level :

Sl. No.	Name of Posts (Para No. of Report of Seventh Central Pay Commission)	Present Grade Pay	Grade recommended by Seventh Central Pay Commission
1	Junior Radiographer of Andaman and Nicobar Islands Administration (7.7.50)	2000	2800

2	Preservation Assistant, Botanical Survey of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (11.16.19)	2000	2400
3	Senior Technical Assistant (Survey), Ministry of Mines (11.29.15)	4200	4600
4	Senior Technical Assistant (Drawing), Ministry of Mines (11.29.15)	4200	4600
5	Technical Officer, Office of Textile Commissioner, Ministry of Textile (11.49.9)	4200	4600
6	Assistant Director Grade-II (Technical), Ministry of Textile (11.49.9)	4600	4800
7	Assistant Accounts Officer, Finance Division of Defence, Ministry of Defence (11.12.140)	4800	5400 (PB-2) on completion of 4 years service
8	Senior Section Officer (Accounts), Ministry of Railways (11.40.83)	4800	
9	Senior Travelling Inspector (Accounts), Ministry of Railways (11.40.83)	4800	
10	Senior Inspector (Store Accounts), Ministry of Railways (11.40.83)	4800	
11	Chemical and Metallurgical Assistant (CMA), Ministry of Railways (11.40.124)	4200	4600
12	Chemical and Metallurgical Superintendent (CMS), Ministry of Railways (11.40.124)	4600	4800
13	Assistant Chemist and Metallurgist, Ministry of Railways (11.40.124)	4800	5400 (PB-2)

A (II) Up-gradation to Apex scale:

Sl. No.	Name of Post (Para No. of Report of Seventh Central Pay Commission)
1	Director General (Indian Coast Guard) (11.12.27)
2	Director General, Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation (11.47.9)
3	Vice President of Income Tax Tribunal, Department of Legal Affairs (11.27.27)
4	Head, National Defence College (NDC), New Delhi (14.21)
5.	Head, National Defence Academy (NDA), Khadakwasla, Pune (14.21)
6.	Head, Defence Services Staff College (DSSC), Wellington (14.21)

B. Cases recommended by Seventh Central Pay Commission in which no action is required :

S.No	Name of Post (Para No. of Report of Seventh Central Pay Commission)	Present Grade Pay	Grade Pay recommended by Seventh Central Pay Commission	Remarks
1	Agriculture Assistant, Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170)	2400	2800	Posts do not exist
2	Gardner overseer, Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170)	2400	2800	
3	Group Level Worker, Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170)	2400	2800	
4	Extension Officer (Agriculture) Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170)	2400	2800	
5	Farm Manager Junior, Government of National Capital Territory of Delhi (11.23.170)	2400	2800	
6	Assistant Store Keeper, Indian Bureau of Mines (11.29.24)	1900	2400	This post already exists in Grade Pay 2400